सत्ता हथियाने को खर्चे गये 100-100 करोड़ रुपए

फ़रीदाबाद (म.मो.) चुनाव आयोग ने बेशक खर्च की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दी लेकिन तीन प्रत्याशियों के लिये इस सीमा का बढना कोई मायने नहीं रखता। इनका तो बजट ही 100-100 करोड़ का रहा। इस बजट के अलावा वह खर्च अलग से है जो उनकी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर कर रही हैं। इनमें से एक पार्टी का तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का बजट तो दस हज़ार करोड़ से भी ऊपर निकल चुका है। दूसरी का भी इससे अधिक नहीं तो कम भी नहीं होगा।

आश्चर्य-चकित एक आम आदमी के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतना पैसा कहां और कैसे खर्च हो सकता है ? लेकिन, यदि वही आम आदमी थोड़ा सा भी जागरूक होकर जानने का प्रयास करे तो बड़ी सरलता से इसका उत्तर जान भी सकता है। गत लगभग एक-डेढ माह से जिस भी अखबार अथवा पत्रिका को देखें तो पैसा खर्च करने वाली इन पार्टियों के नेताओं की तस्वीरों व जुमलों से पटे पड़े हैं। रेडियों टी वी के जिस चैनल को खोलो इन्हीं की 'गाथा' सुनने को मिलती है। शहरों, गांवों की गली मुहल्लों में उनके पोस्टर तथा गाड़ियों पर लगे भोंपू इनकी विरूदावली गा-गा कर ऐसा माहौल बना देते हैं कि आम आदमी को लगे कि इनके अलावा कुछ भी नहीं।

चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद तो इस प्रचारतंत्र में कई गुणा और वृद्धि हो जाती है। भाड़े की गाड़ियां, उन पर लगे भोंपू, उनमें लदे भाड़े के मलंग, सभा स्थलों व नुक्कड़-सभाओं में जुटती भाड़े की भीड़, क्षेत्र भर की गलियों में पटे पड़े बड़े-बड़े पोस्टर, हर खम्बे पर लगे छोट-बड़े होर्डिंग आदि के अलावा वोटरों को बंटने वाली शराब व पैसा तो अलग से है ही।

प्रचारतंत्र पर खर्च होनेवाला पैसा बेशक किसी वोटर की जेब में नहीं जाता, लेकिन यह सीधे-सीधे आम आदमी के दिमाग में घुसता है। सुबह से लेकर शाम तक और वह भी 3 सप्ताह तक लगातार जब एक इंसान कोई बात सुनता है, आते-जाते हर समय वही पोस्टर व बैनर देखता है, चारों ओर भोंपू बजाती उसी तरह की गड़ियां देखता है तो उसके दिमाग में इसका गहरा असर होता है और एक साधारण दिमाग़ का व्यक्ति यह मान बैठता है कि जो कुछ इस प्रचार में कहा जा रहा है वही सत्य है। इसी लिये प्रचारतंत्र पर खर्च किया गया पैसा वोटरों में नकद बांटने से भी कहीं ज़्यादा प्रभावी होता है।

इसके अलावा दूसरे प्रत्याशियों के वोट कटवाने की गरज से 'वोट कटुवा' उम्मीदवार खड़े करने पर भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। ऐसे उम्मीदवार से जिसके सबसे ज़्यादा वोट कटने की संभावना होती है वह मोटी रकम देकर उसे बैठाता है। .

फरीदाबाद में ऐसे ही एक उम्मीदवार को एक तथाकथित बड़े राष्ट्रीय दल ने मोटा पैसा देकर खड़ा कर दिया तो एक जाति विशेष की वोटों का भारी नुकसान होता देख दूसरे क्षेत्रीय दल ने कहीं ज़्यादा मोटा पैसा देकर उसे बैठा लिया। न केवल बैठा लिया बल्कि अपने हक में खुले प्रचार के लिये भी उसे इस्तेमाल किया। इस तरह के मामलों में बेशक लेन-देन की कोई रसीद नहीं होती और तो और न लेने वाला कहता है कि मैंने पैसा लिया और न देने वाला कहता कि उसने कुछ दिया फ़िर भी भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि सौदा 5 करोड़ में तय हुआ था।

ऐसे में आम आदमी के लिये समझना जरूरी है कि पार्टियां एवं उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिये इतना भारी भरकम पैसा आखिर क्यों खर्च करते हैं ? क्यों रात-दिन भागे-भागे फ़िरते हैं ? क्यों हरेक के सामने गिड़गिड़ाते फ़िरते हैं ? क्या यह सब वे जनता की सेवा करने के लिये करते हैं ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। केवल राजसत्ता में हिस्सा पाकर जनता को लूटने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिये। एक बार सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाने पर खर्चे गये धन का सौ गुणा तक वसूल लेना इनके लिये कोई मुश्किल काम नहीं होता। सत्ता में हिस्सा न भी मिले तो भी विपक्ष में बैठकर भी मोटी कमाई का सिलसिला ये लोग बना ही लेते हैं।

जानकार बताते हैं कि एक उम्मीदवार ने विपक्षी विधायक होते हुए भी सरकार से जितना लाभ उठाया उतना तो कई सत्तारूढ विधायक भी उठा नहीं पाये। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में हुए सी एल यू (भूमि का उपयोग परिवर्तन) यानी कृषि भूमि को रिहायशी, रिहायशी अथवा औद्योगकि को व्यापारिक में परिवर्तित करवाने के अधिकतर मामले इसी उम्मीदवार की सिफ़ारिश पर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र हड्डा ने करके दिये हैं।

बल्कि विपक्ष में रहने का लाभ कई बार ज़्यादा हो जाता है। जनहित का कोई काम कराने की बात आये तो ऐसे नेता झट से यह कह कर पल्ला झाड़ लेते हैं कि वे विपक्ष में होने की वजह से फ़िलहाल कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं हैं, उनकी सरकार आयेगी तब देखेंगे। इनमें से एक उम्मीदवार ऐसा है जिसे पैसे के दम पर कहीं से भी चुनाव जीतने का भयंकर घमंड रहा है जो इस बार टूटना निश्चित है। इस बड़बोले ने तो यहां तक भी शेखी बघार दी थी कि टिकट न मिलने पर निर्दलीय भी लड़ेगा। अनपढ ठूंठ होते हुए भी पढे-लिखे उच्चाधिकारियों को सार्वजनिक रूप से धमकाने व धमका कर ब्लैकमेल करना इसका पेशा रहा है गत 10 वर्षों से। घमंड इतना कि मुख्यमंत्री तक को भी आंखें दिखाने में कभी कोई संकोच नहीं रहा। और महत्वाकांक्षा इतनी कि सरदार पटेल जैसा केन्द्रीय गृहमंत्री एवं राज्य का मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देखने लगा। लेकिन इसकी 16 मई को अक्ल ठिकाने आ जायेगी।

एक उम्मीदवार ऐसा भी है जिसका इस इलाके से कोई ताल्लुक न होते हुए भी केवल दो जातियों के दम पर चुनाव जीतने का इरादा है। एक जाति के तो वे खुद हैं ही दूसरी जाति वाले ने उन्हें अपनी जाति के वोटों की गारंटी वाला टिकट दे दिया। टिकट देने वाले नेता के कारनामें इतने 'बढिया' रहे हैं कि खुद तिहाड़ जेल में सज़ा भुगत रहे हैं।

प्रदेश में एक ब्राह्मण बहुल सीट पर सत्तारूढ दल के एक विधायक की नज़र टिक गयी। यह दल तो अपने मौजूदा सांसद के चलते यहां से टिकट नहीं दे सकता था। लिहाजा वे मुख्य विपक्षी गठबंधन के छोटे घटक के सुप्रीमो को पूरे 100 करोड़ का लालच दे आये। लेकिन बड़े घटक के बड़े दादाओं ने टांग अड़ा दी-भला उनकी हिस्सा पत्ती के बिना इतना बड़ा सौदा कैसे सिरे चढ़ सकता था। इस बीच बात खुल गयी तो बीच में ही रह गयी। इस सीट पर अन्ततः बड़े घटक ने अपना उम्मीदवार बाहर से लाकर पैराशूट से उतारा जिसकी कीमत वसूली 25 करोड़।

इस संसदीय क्षेत्र की बगल वाली सीट को एक अनजान उम्मीदवार ने 25 करोड़ में गठबंधन के इसी घटक से खरीदा। खरीद-फ़रोक्त की इस राजनीति में अन्त में गालियां मतदाताओं को ही मिलती है कि वे आंख खोल कर वोट नहीं डालतें।

कैसीनो के मुकाबले में सट्टेबाज उतरे

फ़रीदाबाद (म.मो.) पुलिस के संरक्षण एवं आशीर्वाद के चलते शहर में कैसीनो का धंधा दिन दूनी रात चौगुणी तरक्की कर रहा है। 'मज़दूर मोर्चा' के गतांकों में इस बाबत विस्तृत खबरें प्रकाशित होने के बाद कैसीनो संचालक तो कुछ ठिठके, कुछेक ने तो धंधा बिल्कुल बंद करके अपनी आई डी ही समाप्त करा दी, लेकिन कुछेक ने 4-5 दिन बाद फ़िर से धंधा शुरू कर दिया। जानकार बताते हैं कि धंधा बन्द होने से जब पुलिस की आमदनी पर चोट पड़ी तो खुद पुलिस ने ही उन्हें प्रोत्साहित करके कैसीनो चलवाने शुरू कर दिये हैं।

जैसा कि गतांक में बताया गया था कि कैसीनो में जीतने वाले को 100 के बदले 3600 मिलते हैं; इसके मुकाबले सट्टेबाज़ों ने अपनी ग्राहकी बढ़ाने के लिये 100 के बदले 10 000 देने की घोषणा कर दी है। सट्टेबाज़ी के इस धंधे में कम्प्यूटर अथवा टेलिफ़ोन का कोई काम नहीं है। इस धंधे में ग्राहक अथवा खिलाड़ी जिसे इनकी भाषा में 'फंटर' कहा जाता है, को न्यूनतम 10 रुपये जमा करने पर एक पर्ची पर वह नम्बर लिख कर दिया जाता है जिस पर फंटर पैसा लगाना चाहता है। इस नम्बर के निकल आने पर फंटर को सौगुना पैसा बतौर जीत-राशी (कमीशन काट कर) तुरंत दे दी जाती है।

नम्बर बुकिंग अथवा पैसा लगाने का यह धंधा कोई चोरी-छिपे या दूर दराज के जंगलों में नहीं बल्कि शहर के बीच में खुले आम चल रहा है। थाना एन आई टी क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नंगेपन व बेखौफ़ तरीके से सड़क पर कुर्सी-मेज़ लगा कर किया जा रहा है। एन एच-5 के कई ब्लाकों व गांधी कॉलोनी (स्टेशन के सामने)में कुल मिलाकर 30 लोग इस तरह का धंधा कर रहे हैं।

पूछने पर ये धंधेबाज बताते हैं कि इसमें डरने की क्या बात है? वे कोई गलत काम थोड़े ही कर रहे हैं। कोई आदमी आता है उन्हें कुछ रुपया दे जाता है, जिसकी वह एक पर्ची बना कर उसे दे देते हैं। यदि उसका नम्बर निकल आता है तो शाम को वह अपना 'ईनाम' ले जाता है। इसमें ग़लत क्या है? इसके अलावा प्रत्येक बुकी पुलिस को 15 से 20 हज़ार तक की मंथली एडवांस देता है; फ़िर डर काहे का, क्यों न बेखौफ़ होकर सड़क पर टेबल लगा कर धंधा करें? इसी निर्भयता के चलते सुबह 5 बजे, शाम 6.50 और रात 10.25 पर नम्बर देखने वालों का मजमा इन बुकियों के पास लग जाता है। सट्टेबाज़ी के इस जाल में स्कूली बच्चे सबसे अधिक फंसते हैं। जेब खर्ची से लेकर जो भी उसके पास होता है वे सब इसमें लगा देते हैं। इसके बाद फ़िर वे घर में चोरी करना सीखते हैं और बाद में, पैसा प्राप्ति के लिये जहां कहीं भी जो कुछ करना पड़े वे करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन जनविरोधी सरकार व इसकी पुलिस को क्या फ़र्क पड़ता है? बूढा मरे या जवान इन्हें तो हत्या से काम। समाज और देश उजड़ता है तो उजड़े इन्हें तो अपनी मंथली से काम।

इतना खुला खेल पुलिस कमिश्नर की सहमति के बग़ैर संभव नहीं हो सकता।

प्रशासनिक अव्यवस्था : चुनाव से एक दिन पहले स्कूल कॉलेज बंद

फ़रीदाबाद (म.मो.) 10 अप्रेल को चुनाव डयूटी कराने हेतू ज़िला प्रशासन ने तमाम प्राइवेट स्कूलों व कॉलेजों की बसों को 9 अप्रेल को प्रातः 8 बज़े ही कब्ज़े में ले लिया। इस लिये इन तमाम संस्थाओं को जबरी अवकाश घोषित करना पड़ा।

चुनाव के लिये अतिरिक्त वाहनों की जरूरत पड़ती है, यह बात तो समझी जा सकती है परन्तु इसके नाम पर उन तमाम संस्थानों का, जिनमें पढने व पढाने का तमाम खर्च जनता खुद वहन करती है, बन्द करा देने को सरकारी दादागिरी नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। विदित है कि तमाम स्कूल-कॉलेज दोपहर 2-3 बजे तक ही चलते हैं। यदि सरकार चलाने वालों में थोड़ी भी संवेदनशीलता एवं जनहित की समझ होती तो वे इन बसों को 2-3 बजे के बाद भी तो कब्ज़े में ले सकते थे। दरअसल सरकारी अधिकारियों को काम करने में कम तथा अपना अधिनायकत्व दिखाने में कहीं ज़्यादा रूचि होती है।

यह भी किसी से छिपा नहीं है कि सरकारी स्कूल-कॉलेजों में तो पढाई-लिखाई का काम अब बचा नहीं; जो थोड़ा-बहुत प्राइवेट क्षेत्र में बचा है वह सरकार को सुहाता नहीं। चुनाव ड्यूटी हो या सरकारी नेताओं की चुनाव रैलियां, पहला कहर इन्हीं प्राइवेट स्कूल बसों पर टूटता है। किसी अधिकारी की सिफ़ारिश पर किसी बच्चे को दाखिला न मिले तो भी इन्हीं बसों को हथियार बनाया जाता है। सरकारी एवं प्रशासनिक अधिकारों के दुरूपयोग के चलते ये बसें प्राइवेट स्कूलों की सबसे कमज़ोर नस बन कर उभरी हैं।

जहां तक सवाल है सरकारी परिवहन व्यवस्था का तो उसे कोई पूछने वाला ही नहीं। इसी शहर के रोडवेज़ डिपो में 125-150 बसें खूब बढिया ढंग से चल रही थी। डिपो भी मुनाफ़े में रहा करता था। धीरे-धीरे ड्राइवर, कंडक्टर व मिस्त्री आदि खत्म होते चले गये। बसें खड़ी-खड़ी जंग खाने लगी। इस पर भारत सरकार ने 200 नई बसें और खरीद कर यहां खड़ी कर दी। तय हुआ कि इन्हें नगर निगम चलायेगा। दो साल तक इन्हें खड़ा रखने के बाद यह काम हरियाणा रोडवेज़ को सौंपा गया। अकुशल एवं भ्रष्ट प्रबन्धन के चलते इनमें से बमुश्किल 100 बसें बची हैं वे खटारा हालत में और जो दिन प्रति दिन इनके चलाने से घाटा हो रहा है वह अलग से। कुल मिलाकर सरकार अपने संसाधनों को बर्बाद करके जनता के संसाधनों को हड़पने की फ़िराक में ही हमेशा लगी रहती है। यह भी तय है कि जब तक सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्ट, नाकारा, निकम्मे बल्कि चोर लोग़ बैठे रहेंगे ज़िला एवं निचले स्तर पर यही सब चलता रहेगा।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा के 1-15 अप्रैल 2014 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय राजनीतिक, प्रशासकीय व स्थानीय मुद्दों पर लेख पढने को मिले। सभी लेखों का स्तर काफ़ी अच्छा व सराहनीय है। पुलिस विभाग से सम्बन्धित लेखों 'महिला सुरक्षा व सम्मान का ढोल बजाने वालों ने ही ढोल फाड़ा', 'कैसीनो का बढता कारोबार रोजाना एक करोड़ का व्यापार', 'कानून की धज्जियां उड़ाने में थानेदार हिम्मत सिंह की हिम्मत' तथा 'हत्या केस 'निर्दोष बंदी कांड' द्वारा पुलिस व न्यायायिक व्यवस्था के हाथों आम लोग़ों के पीड़ित होने तथा उनकी दुर्दशा का सटीक वर्णन किया गया है। वास्तव में इसका प्रमुख कारण है प्रशासकीय व्यवस्था का किसी के प्रति जवाबदेह न होना। मध्य काल में शेरशाह सूरी ने गांव के मुखिया को ही शान्ति व व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिम्मेदार बना दिया था। यदि किसी गांव में कोई चोरी हो जाती थी और चोर का कुछ पता नहीं चलता था तो गांव के मुखिया को ही सारा हरजाना भरना पड़ता था। शेरशाह का विश्वास था कि गांव के मुखिया की जानकारी के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। इसलिए पूरी प्रशासकीय व्यवस्था को जवाबदेह बनाना अत्यंत आवश्यक है जिससे आम लोग़ों को कुछ राहत मिल सके।

मोदी सम्बन्धित लेखों 'मोदी साहब...सवाल क्यों नहीं लेते ?', 'संघ, सरदार और मूर्ति' तथा 'अपनों के अपने नहीं मोदी' में मोदी के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन किया गया है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी को भाजपा का एकमात्र नेता के रूप में पेश किया जा रहा है और सारे निर्णय एक व्यक्ति (मोदी) द्वारा लिए जा रहे हैं। यदि कोई वरिष्ठ भाजपा नेता मोदी से सहमत नहीं है तो उसे भी हाशिए पर धकेलने में कोई संकोच व देरी नहीं लगती। लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, सुष्मा स्वराज, लालजी टंडन, जसवंत सिंह आदि वरिष्ठ नेताओं को भाजपा में अस्तित्वहीन बना दिया गया है। यह हालत तो तब है जबकि अभी मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा में मोदी का विरोध करने का कोई साहस नहीं कर सकेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसका वही हाल होगा जैसे मोदी ने गुजरात में अपने विरोधियों का किया है। केशु भाई पटेल, हरेन पांड्या आदि को हाशिए पर लगा दिया। इसके अतिरिक्त मोदी पर एक विरोधी भाजपाई नेता की हत्या करवाने का भी आरोप लगाया जाता रहा है।

वास्तव में मोदी का व्यवहार एक तानाशाह की तरह है। चुनाव रैलियों में मोदी सीना तानकर बोलते हैं और विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए श्रोताओं से खूब तालिया बटोरते हैं, जिनका मीडिया खूब प्रचार करता है। परन्तु मोदी किसी भी मीडियाकर्मी के सवालों को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें आशंका है कि सवालों के दौरान उनके झूठे प्रचार का पर्दाफ़ाश हो जाएगा। मोदी ने अपने ख़िलाफ़ हो रहे विरोध से बौखलाकर जहां आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और केन्द्रीय रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी को पाकिस्तानी एजेंट कहा वहीं केरल में एक चुनाव सभा में उसने वहां की कांग्रेस सरकार पर केरल को पर्यटन केन्द्र की जगह आतंकवाद की नर्सरी बनाने का आरोप लगाया। 'मज़दूरों का चुनावी घोषणापत्र' लेख मौलिक व साहसिक है। इस कार्य के प्रति किसी भी राजनीतिक दल विशेषकर वामपंथी पार्टियों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि यह उनका उत्तरदायित्व था। इस लेख ने 'मज़दूर मोर्चा' नाम को सार्थक कर दिया है।

-डॉ. जुगल किशोर गुप्ता